INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

कृषि-विविधीकरण एवं आत्म-निर्भर भारत
(Agro- Diversification and Self-Reliant India)

अनुपमा सिंह
(इतिहास विभाग)
राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/03.2022-85565737/IRJHIS2203006

प्रस्तावना :

भारत की लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन एक सौ तीस करोड़ आबादी वाले देश भारत के लिए बढ़ती जनसँख्या, बेरोजगारी, आमदनी के स्रोतों में कमी, अर्थव्यवस्था के विकास की धीमी गति आदि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान हमेशा ही महत्त्वपूर्ण रहा है। आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं, विभिन्न कृषि नीतियों एवं साठ के दशक में क्रियान्वित हरित-क्रान्ति ने न केवल भारत के लिए खाद्यान्नों की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की अपितु भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर भी बनाया। वैसे तो परंपरागत भारतीय कृषि की विशेषता सीमान्त किसान एवं छोटे जोत हैं परन्तु वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहा है, नित्य प्रति परिवर्तनशील तकनीक एवं बाज़ारीकरण को देखते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

अगर कृषि क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाये जाएं तो एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कृषि के विविधीकरण की जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी गति प्रदान करेगा। प्राचीन काल से भारतीय किसान परंपरागत तरीकों से खेती करता आया है परन्तु **कृषि-विविधीकरण न केवल प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न जोखिमों को कम करेगा बल्कि कृषि में टिकाऊ उत्पादन, स्थायी आमदनी और रोजगार में स्थायित्व प्रदान करेगा।**

कृषि-विविधीकरण के अंतर्गत विभिन्न कृषिगत गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन, मत्स्य पालन, बागवानी इत्यादि को सम्मिलित करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व में पचहत्तर प्रतिशत खाद्य आपूर्ति मात्र कुछ अनाज और दाल

वाली फसलों की खेती पर निर्भर करती है और यह निर्भरता प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, जलवायु परिवर्तन, कीट और रोगों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है जोकि में कृषि पर्यावरण के संतुलन के लिए हानिकारक होती है। ऐसे में कृषि-विविधीकरण न केवल इन चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा अपितु किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करेगा जिसका सीधा प्रभाव पोषण, सामाजिक और आर्थिक विकास पर पड़ेगा।

भारतीय कृषि क्षेत्र वर्तमान युग में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव से उत्पन्न आंतरिक एवं वाह्य दबावों का सामना कर रही है। परन्तु विगत वर्ष 2020 जिस तरह सम्पूर्ण विश्व के लिए आपातकाल का वर्ष रहा जिसमें तमाम विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था चरमरा गयी, भारतीय कृषि ने कोविड-19 की समस्या से जूझते हुए भारतीय अर्थ-व्यवस्था को सहारा दिया एवं अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने में सफल रही।

वैश्वीकरण के दौर में विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए न केवल भारतीय कृषि में विविधता लाना आवश्यक हो गया है अपितु निचले स्तर तक प्रत्येक किसान को भी अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लाना जरूरी है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार व किसानों को यथोचित कृषि-विविधीकरण नीति लागू करना होगा। कृषि-विविधीकरण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए इसके विभिन्न आयामों जिनमें बहु फसली योजना, उन्नत बीज, कृषिगत नवीन तकनीक, कृषि की जैविकीय प्रणाली (जैविक कृषि, मृदा-संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण), अन्य कृषि आधारित गतिविधियां जैसे डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन, मत्स्य पालन, बागवानी इत्यादि, कृषि आधारित उद्योग एवं बाज़ार आदि शामिल हैं, पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कृषि-विविधीकरण के आयामों को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से लागू करने से कृषि के उत्पादन, गुणवत्ता, आपूर्ति, खाद्यान्नों की बाजारों तक पहुंच, कृषि आधारित उद्योग एवं रोजगार आदि क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसकी सफलता न केवल किसानों के जीवन-स्तर को सुधारेगी अपितु भारतीय कृषि क्षेत्र में जो छिपी बेरोजगारी है, उसको भी दूर करने में सहायक होगी। कृषि-विविधीकरण के आयाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने के साथ- साथ एक दूसरे के पूरक भी हैं। कृषि-विविधीकरण की प्रक्रिया तभी सफलता के शिखर पर पहुंचेगी जब उन्नतशील बीजों और प्राकृतिक खादों का अधिकतम प्रयोग, नवीन तकनीकों जैसे जल संरक्षण प्रणाली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आदि के माध्यम से कृषि को उन्नत किए जाने का प्रयास किया जाए। कृषि-विविधीकरण के माध्यम से भूमिहीन मजदूरों को भी कृषि की मुख्यधारा में लाया जा सकता है जब अन्य कृषि गतिविधियों जैसे बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे स्थायी आमदनी एवं रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि-विविधीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ सबका साथ सबका विकास का सपना भी साकार होगा।

कृषि विविधीकरण के जहां सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं वहीं इसके नकारात्मक पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। यदि साठ के दशक की हरित क्रांति की बात करें तो एक ओर जहां हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाया वहीं दूसरी तरफ इसका नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया। जैसे भूमि की उर्वरता में कमी, पर्यावरणीय असंतुलन, भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग इत्यादि। ऐसे नकारात्मक प्रभावों से निपटने में जैविक कृषि एक सफल प्रयोग साबित हो सकता

है जिसका उदाहरण सिक्किम राज्य में देखने को मिलता है।

बहुफसली योजना भी कृषि-विविधीकरण की सफलता में सहायक होगी जो कि छोटे एवं सीमांत जोत के किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी। साथ ही साथ कृषि-विविधीकरण की अवधारणा द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता जिसे पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी रेखांकित किया था, को पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

इसके अलावा कृषि-विविधीकरण की प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाने के लिए उत्पादन के साथ-साथ कृषि उत्पादों की बाजारों तक सुगमता से पहुंच को आसान बनाना होगा। गाँवों से बाजारों को जोड़ने के लिए आवागमन की सुविधाएं बढ़ानी होंगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है जिसमें मृदा से लेकर विपणन तक की प्रक्रिया की सुगमता सुनिश्चित हो सके। ऐसे में कृषि-विविधीकरण के साथ-साथ कृषि अनुसंधान एवं कृषि आधारित उद्योगों पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिससे भारतीय कृषि अपने सपनों के धरातल पर पहुंच सके। जैसा कि वर्तमान समय में आत्म-निर्भरता की संकल्पना की गई है, वह तभी अपने साकार रूप में परिलक्षित होगी जब भारत पूरी तरह आत्म-निर्भर होगा। कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की पहल इस सोच को एक सकारात्मक और विकासात्मक दिशा देगी। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत पूरी तरह आत्म-निर्भर देश तभी बनेगा जब भारत का प्रत्येक गांव, प्रत्येक किसान आत्म-निर्भर होगा।

कृषि-विविधीकरण की अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सहायक हो सकती है जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में बदलकर रोजगार के विभिन्न स्रोत उत्पन्न किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हैं और अधिकतर लोगों को बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कृषि गतिविधियां जैसे पशुपालन, डेयरी इत्यादि नवीनतम रोजगारों का सृजन करती हैं और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाती हैं। पारंपरिक कृषि एवं परंपरागत तकनीकों के बदले अगर कृषि-विविधीकरण को नवीनतम एवं प्राकृतिक तकनीकों के साथ अपनाया जाए तो किसानों का कृषि उत्पादन न केवल बढ़ेगा अपितु गुणवत्ता पर आधारित होगा। इसे पिछले कई वर्षों के उत्पादन की मात्रा के आधार पर भी समझा जा सकता है।

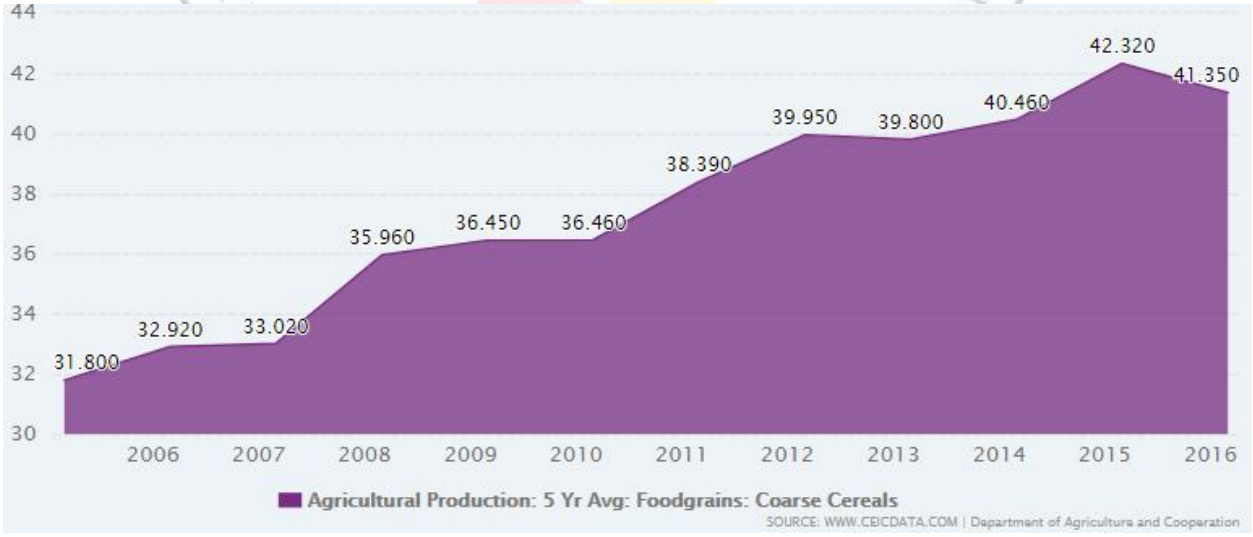

इस प्रकार जहां कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा वहीं कृषि उत्पादन लागत में भी कमी देखने को मिलेगी। इसका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जीरो बजट प्राकृतिक खेती है जिसमें न केवल उन्नतशील बीजों की

जरूरत पूरी होगी बल्कि मिट्टी और पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। उदाहरण के तौर पर एक देशी गाय के गोबर एवं गोमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है जिसमें उत्पादन लागत लगभग शून्य होती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है।

इसके अलावा उत्पादन की लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए बिजली के स्थान पर यदि सोलर पंप का उपयोग किया जाए तो उत्पादन लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

विवरण	विद्युत पंप	सोलर पंप
जोत	10 एकड़	10 एकड़
पंप लागत	रु 50,000/-	रु 20,000/-
प्रयुक्त ईंधन प्रभार (10 घंटे)	(100 यूनिट): रु 800/-	---
अनुरक्षण लागत	रु 1,000/-	रु 500/-
सकल योग	**रु 51,800/-**	**रु 20,500/-**

कम उत्पादन लागत की दर पर अधिकतम उत्पादन की प्रासंगिकता तभी है जब कृषिगत उद्योगों का विकास अधिक से अधिक हो। इसके लिए कृषि आधारित उद्योगों को कृषि क्षेत्रों से जोड़ने की जरूरत है जिसमें उद्योगों को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो सके। इस प्रकार यातायात के खर्चों में कमी आएगी और वाहनों को कम ईंधन की आवश्यकता होगी। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी कम होगा क्योंकि ईंधन की कम खपत से वातावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ वाहनों में ईंधन का कम प्रयोग ईंधनों के आयात के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा जुटाने के भार को कम करेगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगा।

कृषिगत उद्योगों का विकास किसानों के लिए वैकल्पिक खेती का भी अवसर प्रदान करेगा जिसमें किसानों एक निश्चित किस्म की उपज की पैदावार करके औद्योगिक इकाइयों को दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पेप्सिको का पंजाब के किसानों से आलू की एक विशेष किस्म FL-2027 उगाने का समझौता हुआ है।

इन तमाम प्रयासों से कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे भारतीय किसान कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। परन्तु इसके लिए उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ नवीन कृषि प्रणाली और जानकारियों की जरूरत है। किसानों की इस जरूरत को तभी पूरा किया जा सकता है जब जगह-जगह पर कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के साथ- साथ उत्पादन क्षेत्र से विपणन तक कृषि उत्पाद की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए।

चाहे साठ के दशक में हरित क्रांति के माध्यम से भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने की बात हो या फिर कोरोना काल में, जब सभी व्यावसायिक क्षेत्र बंद पड़े थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की बात हो, कृषि क्षेत्र ने हमेशा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को साबित किया है।

कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों, चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के साथ-साथ कृषि-विविधीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

अगर भारतीय कृषि में नवीनतम प्रणाली और सोच को अपनाया जाए तो आने वाले भविष्य में न केवल कृषि क्षेत्र की उपयोगिता बढ़ेगी अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान पहले से कई गुना अधिक होगा। जहाँ तक वर्तमान सरकार द्वारा चलाई गई नवीन एवं विशेष पहल **"आत्म-निर्भर भारत"** की बात है, इस संकल्पना को मूर्त रूप तभी दिया जा सकता है जब भारत पूरी तरह से आत्म-निर्भर हो। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आत्म-निर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब यह आत्म-निर्भरता भारतीय कृषि से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में आएगी चाहे वह कृषि तकनीक हो, कृषिगत उपकरण हो या कृषिगत उद्योग।

इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कृषि-विविधीकरण की प्रक्रिया तभी वांछित परिणाम दे पाएगी जब उन्नतशील बीजों और नवीन तकनीकों जैसे जल संरक्षण प्रणाली, प्राकृतिक खादों का प्रयोग आदि के माध्यम से प्रयास किया जाए। कृषि-विविधीकरण के माध्यम से भूमिहीन मजदूरों को भी एक साथ लाया जा सकता है। अन्य कृषिगत गतिविधियाँ जैसे बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो इससे **स्थायी आमदनी एवं रोजगार की संभावना** बढ़ेगी जिससे गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ **सबका साथ सबका विकास** का सपना भी साकार होगा। इसकी सफलता न केवल किसानों के जीवन स्तर को सुधारेगी अपितु **भारतीय कृषि क्षेत्र में जो छिपी बेरोजगारी है उसको भी दूर करने में सहायक होगी। कृषि-विविधीकरण के आयाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने के साथ ही साथ एक दूसरे के पूरक भी हैं।** कृषि-विविधीकरण की सफलता की गति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उत्पादन के साथ-साथ खाद्यान्नों की बाजारों तक सुगमता से पहुंच को आसान बनाना होगा।

वैश्विक चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए कृषि-विविधीकरण के साथ-साथ कृषि अनुसंधान एवं कृषि आधारित उद्योगों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा शुरू की गई आत्म-निर्भरता की पहल तभी अपने साकार रूप में परिलक्षित होगी जब भारत पूरी तरह आत्म-निर्भर देश बनेगा और यह तभी संभव है जब भारत का प्रत्येक गांव, प्रत्येक किसान आत्म-निर्भर होगा। कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भरता इस पहल को एक सकारात्मक और विकासात्मक परिणाम देने में सहायक होगी।

ऐसे में आने वाले वर्षों में कृषि-विविधीकरण स्थायी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और स्थायी विकास सुनिश्चित करने में एक कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ-सूची :

1. आर्थिक -सर्वेक्षण- 2019-20
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
3. कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय
4. 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए कृषि का रूपांतरण- नीति आयोग की रिपोर्ट
5. किसानों की आय दोगुनी करना-वॉल्यूम –XIV, व्यापक नीति सिफारिशें
6. योजना पत्रिका
7. इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र
8. आम बजट- 2019-20
9. India Year Book- 2021
10. कृषि जागरण पत्रिका